दैनिक जागरण
विनम्रता समस्त गुणों की आधारशिला है

नई शिक्षा नीति पर अमल

लंबे इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति का मसौदा सामने आ गया, लेकिन यह अच्छा नहीं हुआ कि ऐसा होते ही हिंदी को लेकर एक अनावश्यक विवाद छिड़ गया। अब जब यह विवाद शांत हो गया है तब फिर जरूरी यह है कि नई शिक्षा नीति को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि वह नई शिक्षा नीति की ज्यादातर सिफारिशों को अगले दो साल में लागू करने का इरादा रखती है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा वास्तव में हो। नई शिक्षा नीति को लागू करने में तेजी दिखाने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि एक तो इस नीति का मसौदा देर से आ सका और दूसरे, शिक्षा का मौजूदा ढांचा व्यापक बदलाव की मांग करता है। शायद ही कोई इससे असहमत हो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का हमारा ढांचा आज की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। चूंकि समस्याएं प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही शुरू हो जाती हैं इसलिए उनका दुष्प्रभाव माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक नजर आता है। जहां प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम के साथ ही पठन-पाठन के तौर-तरीकों को दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है वहीं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अंकों की होड़ को दूर करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब नई शिक्षा नीति की सिफारिशों पर न केवल विभिन्न राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी आम सहमति कायम हो सके। यह तभी संभव होगा जब नई शिक्षा नीति के मसौदे पर राजनीतिक संकीर्णता से मुक्त होकर विचार किया जाएगा।

किसी के लिए भी समझना कठिन है कि माध्यमिक शिक्षा के केंद्रीय और राज्यों के बोर्ड इस पर सहमत क्यों नहीं हो सकते कि परीक्षाओं में अंकों की होड़ खत्म हो? निःसंदेह परीक्षाओं में अंकों का कुछ न कुछ महत्व तो रहेगा ही, लेकिन इसका औचित्य नहीं कि छात्रों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन केवल उन्हीं के आधार पर किया जाए। यह वक्त की मांग है कि विभिन्न शिक्षा बोर्ड एकमत होकर कार्य करें। परीक्षाओं में अंकों की होड़ समाप्त करने के साथ ही एक बड़ी जरूरत यह भी है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। अलग-अलग तरह के पाठ्यक्रम असमानता की खाई को चौड़ा करने का ही काम कर रहे हैं। आखिर माध्यमिक शिक्षा का ढांचा ऐसा क्यों नहीं हो सकता जिससे इस स्तर की शिक्षा पूरी करने वाले छात्र करीब-करीब एक समान धरातल पर नजर आएं? माध्यमिक शिक्षा के मुकाबले उच्च शिक्षा कहीं अधिक गंभीर सवालों का सामना कर रही है। उच्च शिक्षा के अधिकांश संस्थान डिग्रियां बांटने के केंद्र बनकर रह गए हैं। इन संस्थानों से निकलने वाले अधिकांश युवा उद्योग-व्यापार जगत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेहतर हो कि उच्च शिक्षा का स्तर इस तरह सुधारा जाए जिससे हमारे युवा किसी न किसी हुनर से लैस हों। उच्च शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि उसे कौशल विकास से जोड़ा जाए।

उत्तराखंड को उम्मीदें

15वें वित्त आयोग के सामने उत्तराखंड तीसरी बार अपना पक्ष रखने में कामयाब रहा है। दो बार तो आयोग के दल ने विभिन्न हिस्सों में घूमकर राज्य की विषम परिस्थितियों, जरूरतों, अवस्थापना सुविधाओं की हालत का विस्तार से जायजा लिया। अभी दो दिन के दौरे पर आए आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में दो सदस्यीय दल ने केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, साथ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड को उम्मीद है कि इस बार आयोग से उसे मायूसी हाथ नहीं लगेगी। इससे पहले 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के चलते राज्य को बीते पांच वर्षों से आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। उक्त सिफारिश के आधार पर राज्य को मिलने वाली केंद्रीय मदद में कमी आई। केंद्र से मिलने वाली ब्लॉक ग्रांट, विशेष आयोजनागत सहायता और विशेष केंद्रीय सहायता पर रोक लगने से सालाना 2000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ने से नुकसान की कुछ हद तक पूर्ति हुई, लेकिन विकास योजनाओं में केंद्र से मिलने वाली राशि में कमी आई। अब जीएसटी लागू होने से राज्य की आमदनी में 39 फीसद की कमी हो चुकी है। राज्य के सामने दो बड़ी चुनौती हैं। एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अवस्थापना विकास की धीमी गति और दूसरी चुनौती वन अधिनियम व पर्यावरणीय प्रतिबंधों के चलते ऊर्जा, जल व वन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का बेहद सीमित उपयोग। यही वजह है कि राज्य की ओर से लगातार ग्रीन बोनस की मांग की जा रही है। पर्यावरणीय सेवाओं और पारिस्थितिकी संतुलन में उत्तराखंड की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाने के बावजूद इस मांग को माना नहीं जा सका। वहीं बड़े पर्वतीय भू-भाग में बुनियादी ढांचा बेहद लचर है। ऐसे में पर्यटन जैसे असीम संभावनाओं वाले क्षेत्र का दोहन नहीं हुआ। ऑलवेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन और भारतमाला प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र में नई संभावनाएं जगी हैं, लेकिन राज्य के भीतरी बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त मदद आवश्यक है। राज्य के नीति नियंताओं ने अपनी इन्हीं चिंताओं से 15वें वित्त आयोग को अवगत कराया है। उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में राज्य को अधिक मदद मिलेगी।

उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती

संजय गुप्त

तमाम मुश्किलों के बावजूद चूंकि मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है इसलिए उसके पास अपने वायदों को पूरा करने से बचने के लिए किसी दलील की कोई गुंजाइश नहीं है

मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और उसका काम तेजी पकड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही लंबी चुनाव प्रक्रिया के कारण ठप सी रही शासन प्रक्रिया के दुष्परिणाम भी दिखने लगे हैं। अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिख रही है और बेरोजगारी का सवाल भी सिर उठाने लगा है। चूंकि प्रधानमंत्री को इसका अहसास है इसलिए उन्होंने दो नई कैबिनेट समितियों निवेश-विकास और रोजगार-कौशल विकास का गठन खास तौर पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया है। गृहमंत्री अमित शाह को इन दोनों समितियों के साथ शेष छह समितियों में भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पिछली सरकार के करीब 40 प्रतिशत मंत्रियों को इस बार मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी है। इसके पीछे इरादा यही है कि सरकार की कार्यशैली को गति और ऊर्जा मिले। मोदी सरकार को अपनी दूसरी पारी शुरू करते हुए इस पर भी ध्यान देना है कि पिछली सरकार में जो लक्ष्य तय किए गए थे उनमें कहां कितनी सफलता मिली? निःसंदेह मोदी सरकार की कई बड़ी योजनाओं का काफी कुछ असर जमीन पर देखने को मिला है, लेकिन देश के एक हिस्से और खास तौर पर उत्तर भारत में अभी भी अनियोजित विकास की समस्या बनी हुई है। इस अनियोजित विकास के कारण दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के अलावा देश के अन्य महानगरीय क्षेत्र का ढांचा चरमराता हुआ दिख रहा है। चूंकि सभी इससे परिचित हैं कि बड़े शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं और आने वाले समय में वे आबादी के दबाव का और अधिक सामना करेंगे इसलिए उनके सुनियोजित विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अनियोजित विकास तमाम समस्याओं को जन्म देने के साथ ही शहरी जीवन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

एक अर्से से हमारे नेता देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखाते चले आ रहे हैं, लेकिन हम इस पर गौर नहीं कर पा रहे हैं कि विकासशील से विकसित देश की यात्रा तय करने के लिए फिलहाल जिन मानकों को अपना रहे हैं उनसे बात बनने वाली नहीं है। इसलिए बनने वाली नहीं, क्योंकि विकास के हमारे जो मानक हैं वे गुणवत्ता से हीन हैं और शार्टकट तरीकों या फिर किसी तरह के जुगाड़ से लैस हैं। विकास के ऐसे मानकों से विकसित राष्ट्र की इमारत खड़ी करना संभव नहीं, फिर भी मौजूदा समय विकास कार्यों में लगी सरकारी एजेंसियां जैसे-तैसे काम करने की प्रवृत्ति से ग्रस्त दिखती हैं। वे गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं और इसी कारण उनकी ओर से जो आधारभूत ढांचा तैयार किया जाता है वह थोड़े समय बाद ही अपर्याप्त दिखने लगता है या फिर चरमराने लगता है। समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं, क्योंकि औसत भारतीय हर वक्त शार्टकट की ताक में रहता है। देश की राजधानी के वीआइपी इलाके यानी लुटियन दिल्ली से लेकर आम शहरों तक में आधारभूत ढांचे के निर्माण में कहीं पर्यावरण की अनदेखी होती है तो कहीं शहरीकरण संबंधी योजनाओं के बुनियादी नियमों का उल्लंघन होता है। यह कभी पैसे बचाने के लिए होता है तो कभी जल्द काम निपटाने की कोशिश में। मानकों की अनदेखी विभिन्न उत्पाद एवं उपकरण तैयार करने में भी होती है। जुगाड़ केवल वह वाहन ही नहीं है जिसे किसी इंजन के सहारे तैयार कर लिया जाता है और फिर उसे सवारियां या सामान ढोने के काम में लाया जाता है। यह एक प्रवृत्ति भी है। मुश्किल यह है कि कुछ लोगों की ओर से जुगाड़ की तारीफ की जाती है, जबकि वह अव्यवस्था-अराजकता का प्रतीक है। आखिर सड़कों पर जोखिम भरा जुगाड़ नामक वाहन क्यों चलना चाहिए? यह ठीक है कि अब कहीं-कहीं जुगाड़ की जगह ई रिक्शा चलने लगे हैं, लेकिन उनकी भी गुणवत्ता ठीक नहीं। इसके बावजूद उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके नियमन की भी कोई सही व्यवस्था नहीं की जा रही है। अगर उनकी गुणवत्ता बेहतर करके उनका नियमन सही तरह से किया जाए तो वे सुरक्षित बनने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी सहायक बन सकते हैं। जैसे गुणवत्ताहीन ई रिक्शे का चलन बढ़ रहा है वैसे ही अन्य अनेक ऐसे काम हो रहे हैं जो बेहतर नियमन की मांग करते हैं।

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार के सामने विकास को सही रूप देने के साथ ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की भी चुनौती है। इसी के साथ जो निर्धन एवं वंचित हैं उन्हें मुख्यधारा में भी लाने की चुनौती है। चूंकि इस चुनौती का सामना करने के लिए जितना धन चाहिए उतना सरकार के पास है नहीं इसलिए उसे इसके प्रति सचेत रहना होगा कि बड़ी योजनाओं में धन का अपव्यय न होने पाए। अरबों रुपये की योजनाओं के क्रियान्वयन में तनिक भी देरी का मतलब है उनकी लागत में करोड़ों रुपये की अनावश्यक वृद्धि। धन के इस अपव्यय को प्राथमिकता के आधार पर रोकना होगा। इसी तरह उस भ्रष्टाचार को भी रोकना होगा जो ठेकेदारों और इंजीनियरों की साठगांठ से विभिन्न निर्माण कार्यों में हो रहा है। खराब निर्माण कार्य अर्थव्यवस्था को नुकसान ही पहुंचाता है।

मोदी सरकार को चाहिए कि वह अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन की गति को बढ़ाए। तेज और विश्वस्तरीय विकास के मामले में अक्सर चीन का उदाहरण दिया जाता है तो इसीलिए कि उसने कहीं तेजी से गुणवत्तायुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण करने में सफलता हासिल की है। चीन के मुकाबले भारत बहुत पीछे दिख रहा है। मोदी सरकार को न केवल इस पर ध्यान देना होगा कि शहरी ढांचा सही तरह निर्मित हो, बल्कि यह भी देखना होगा कि ग्रामीण और अर्द्धशहरी इलाकों में भी हर क्षेत्र में मानकों के अनुरूप काम हो। अपने देश में एक बड़ी आबादी अनियोजित कालोनियों या फिर अनधिकृत बस्तियों में रहती है। ऐसे आवासीय क्षेत्र अन्य समस्याओं को जन्म देने के साथ ही पर्यावरण का संकट बढ़ाने का भी काम करते हैं। पर्यावरण के प्रति सजगता तभी काम आएगी जब हर क्षेत्र में मानकों के हिसाब से काम होगा। ऐसी नीतियों का निर्माण और उन पर अमल आवश्यक है जिससे लोगों की दैनिक चर्या पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा सके। खराब पर्यावरण लोगों की सेहत के लिए संकट पैदा करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने का काम करता है।

केंद्र की अधिकांश योजनाएं राज्यों को ही लागू करनी होती हैं। आज देश के 16 राज्यों में भाजपा या फिर उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, मेघालय, नगालैंड में गठबंधन सरकारें हैं। तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके हाथ से निकल गए हैं। दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़ दें तो कहीं भी भाजपा या उसके सहयोगी दल की सरकार नहीं। कई गैर भाजपा शासित राज्य केंद्र से असहयोग भी कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए राज्यों का सहयोग लेकर अपनी नीतियों को लागू करना और बेहतर नतीजे देना मुश्किल हो सकता है। इस मुश्किल के बावजूद चूंकि मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है इसलिए उसके पास अपने वायदों को पूरा करने से बचने के लिए किसी दलील की कोई गुंजाइश नहीं है।

response@jagran.com

गठबंधन की गांठ खुलने के बाद

हास्य-व्यंग्य

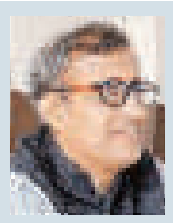

संतोष त्रिवेदी

राजनीति में अगर प्लान 'ए' नाकाम हो जाए तो झट से प्लान 'बी' आगे बढ़ा दो। लड्डू की तरह दोनों हाथों में विकल्प रखो

चुनाव से पहले जिस मजबूत निष्ठा से विरोधी को निपटाना होता है, परिणाम उलट होने पर श्रद्धापूर्वक वही सहयोगी निपट भी जाता है। निष्ठा और सिद्धांत राजनीतिक आत्मा की सगी संतानें हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों सही समय पर आत्मा की पुकार सुन लेती हैं। शायद इसीलिए सनातन काल से आत्मा अजर-अमर है। लोकतंत्र में उसे तनिक भी खरोंच नहीं आती। विशेषज्ञों की सलाह से उस पर गठबंधन-महागठबंधन का लेप भी लगाया जाता है ताकि वह 'अमर' रहे। इस बार भी यही हुआ। कुछ लोग बुरी तरह जीते। कुछ लोग अच्छी तरह से हारे। जो लोग 'प्री-पोल' में लड्डू बांट रहे थे', 'पोस्ट-पोल' में खुद बंट गए। जिनके 'हाथ' कट गए उन्होंने यह सोचकर संतोष कर लिया कि 'जो हुआ, सो हुआ।' लोकतंत्र के रण में निष्ठा और सिद्धांत खेत रहे। इतनी जोर की हवा आई कि गठबंधन की गांठ खुल गई।

अभी कल की ही बात है, शाम के धुंधलके में टहल रहा था कि अंधेरे में अचानक दो आकृतियां नजर आईं। परिचय पूछा तो सुनाई पड़ा, 'हम गठबंधन की गांठ हैं। अभी-अभी मिलावट से मुक्त हुए हैं। यह खबर हमारे लोगों को जल्द से जल्द दे दो। हमारा मिशन पूरा हुआ।'

'लेकिन आपने तो इस बंधन के लिए खूब कसमें खाई थीं। इतनी जल्दी सब भूल गईं?' हमने खबर निकालने की कोशिश की। 'आपका बुनियादी सवाल ही गलत है। पहली बात तो यह कि हम कसम नहीं वादे खाते हैं। दूसरी बात, हमारी कसमें जनता भूलती है, हम उससे किए वादे। और हां, राजनीति में जल्दी कुछ नहीं होता। सब मौके से होता है। जब मौका हो, बरसों पुरानी रंजिश भूल जाओ। जब मौका हो, ताजी दोस्ती में आग लगा दो। राजनीति हर पल बलिदान चाहती है। हम वही कर रहे हैं।' आकृति पहले से अधिक आश्वस्त होकर बोली।

'आपने तो मिलन का संकल्प लिया था फिर इसे तोड़ने का खयाल कैसे आया?' गांठ हमारे सामने खुल चुकी थी। इसलिए खुलकर बोलने लगी, 'राजनीति में जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो असल में वह हमारे लिए विकल्प होता है। जनता को भी हर समय विकल्प की तलब लगी रहती है। हम तो उसके सेवादार हैं। इसीलिए विकल्प को अपना शाश्वत सखा बना रखा है। सहयोगियों को इतनी सीधी बात समझ में नहीं आई। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। रही बात इसे तोड़ने की, यह सरासर गलत आरोप है। हमने इसे केवल 'ब्रेक' दिया है। आगे फिर से हम समझेंगे, गांठ जोड़ लेंगे। तब तक इसे 'होल्ड' पर रखेंगे।'

हमें बीज-वक्तव्य की तलाश थी, सो पूछ लिया, 'पर इतनी बड़ी मिलावट को आपने बड़ी खूबसूरती से जमीन पर ला दिया। इससे आपकी मूर्ति खंडित नहीं हुई?'

'देखिए, हम जो भी काम करते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर करते हैं। इस मिलावट को मिट्टी में मिलाने का काम दूसरों ने किया है। हम तो वह करते हैं जो कहते नहीं। उनके लोगों ने तो कहकर भी नहीं किया। चुनाव में हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें 'गणित' समझाया गया था कि देश की जिम्मेदारी हमें मिलेगी पर 'वे' अपना परिवार भी नहीं बचा पाए। ऐसे लोग हमें क्या बचाएंगे?' इसी बीच बगल वाली आकृति बोलने लगी, 'अरे, यह तो 'बंधन' था, जो ताजा-ताजा 'गांठ' से अलग हुआ था। हमने अपने कान उसकी ओर मोड़ दिए। 'बंधन' निराश था, पर हताश नहीं। कहने लगा-'हम विज्ञान के पालक हैं। एक प्रयोग किया, जो विफल रहा। हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं। आगे भी करते रहेंगे। वास्तव में इस हार में हमारी जीत हुई है।' इतना सुनते ही हमारे मुड़े हुए कान खड़े हो गए। हम सहसा पूछ बैठे-'वह कैसे?'

'हमारा काम राजनीति में भले हो, पर हम रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। गठबंधन में भी हमने रिश्ता निभाया, पर दूसरों ने राजनीति की। सत्ता हमारे हाथ नहीं आई, कोई बात नहीं। हार के बहाने हमारा परिवार एक होने जा रहा है, यह बड़ी उपलब्धि है। आखिर, हम जो करते हैं, परिवार के लिए ही तो!' ऐसा कहकर 'बंधन' ने लंबी सांस ली।' मगर आपने कई अवसरों पर कहा है कि आप समाज के लिए राजनीति में हैं?' हमने अपना सवाल उछाल दिया।

'हां, हमने कई मौकों पर कहा है, आगे भी कहेंगे। यहां तक कि हमारी पार्टी ही 'समाज' को समर्पित है। पर अभी मौका दूसरा है। वैसे हमें इस चुनाव ने कई सबक दिए हैं। एक तो यह कि हमेशा दो प्लान तैयार रखो। प्लान 'ए' नाकाम हो जाए तो झट से प्लान 'बी' आगे बढ़ा दो। लड्डू की तरह दोनों हाथों में विकल्प रखो। वास्तव में हम मतों से नहीं प्लान 'बी' से मात खा गए।' ऐसा कहकर बंधन ने गांठ की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | केंद्रीय मंत्रिपरिषद में दलितों (एससी) का प्रतिनिधित्व

(आंकड़े फीसद में)

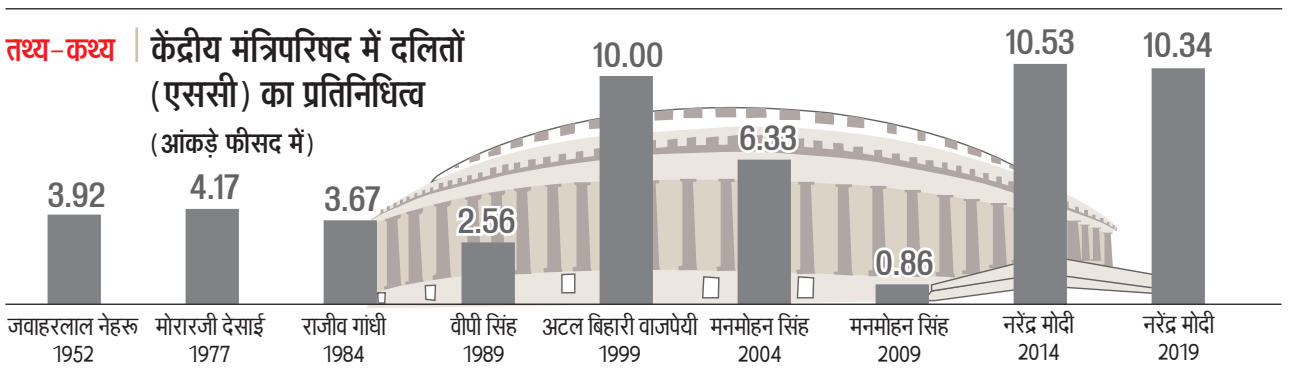

ऊर्जा

तनाव से मुक्ति

तनाव ने मानव जीवन पर गहरा आघात किया है। आज मानव भौतिक संसाधनों की होड़ में बुरी तरह उलझकर रह गया है और बाह्य पदार्थों को ही अपने जीवन में सुख-शांति का साधन मानता है। अगर भौतिक सुख-साधन तनावमुक्त रख सकते तो सभी धनवान सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते। आज निर्धन व्यक्ति भी तनावग्रस्त है, परंतु दोनों के तनावों के स्तरों में अंतर है। तनाव की अभिव्यक्ति दुख, विलाप, चिंता और आवेग के रूप में लक्षित होती है। तनावग्रस्त व्यक्ति सदैव अशांत रहता है। यदि हम प्रकृति की ओर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि यदि आकाश अशांत है तो वायुयान उड़ान नहीं भर सकेंगे, धरती अशांत है तो प्राणिमात्र व्याकुल हो उठता है। इसीलिए तनाव जीवन के विकास को अवरुद्ध कर देता है। तनाव एक विकृति है। शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन व्यक्ति के दैहिक तंत्र को प्रभावित कर मानसिक प्रक्रियाओं में विचलन उत्पन्न करते हैं। आज व्यक्ति समूह का सर्वाधिक हिस्सा अपने अहंकार की तुष्टि में अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा है।

धन, ऐश्वर्य, मान-सम्मान, वैभव, संपदा, सत्ता-शासन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति हरसंभव प्रयास करता है। अन्याय-अनीति एवं भ्रष्ट आचरण से प्राप्त दो नंबर का धन व्यक्ति के आचरण को भ्रष्ट एवं अहंवादी ही बनाएगा। वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप आज व्यक्ति विकृतियों एवं तनाव के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। यदि धनार्जन न्याय एवं नीतिसंगत हो रहा हो तो विकृतियों के आने की संभावना नगण्य हो जाती है। गृहस्थ जीवन के लिए धन आवश्यक है, पर ईमानदारी से किया गया धनोपार्जन विकृतियों से दूर रखता है। आज आवश्यकता है समाज के लोगों की मानसिकता में भ्रष्ट आचरण की विकृति को दूर करने की, बदलने की। अनुशासन, भय एवं दंड की व्यवस्था से ही इस विकृतिजन्य तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका उचित समाधान न हो। तो फिर समाज में व्याप्त विकार भला कैसे दूर नहीं होंगे? इसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे, राष्ट्र को संगठित कर, एकजुट होकर अन्याय व अनीतिपूर्वक संचित करने की विकृति को रोककर समाज को तनावमुक्त करना आज की प्राथमिकता है।

बीना जैन

सूरज पर बड़ी हलचल के संकेत

मुकुल व्यास

सौर धब्बों की मात्रा घटने पर कृत्रिम शांति से चुंबकीय तूफान पैदा होते हैं जो पृथ्वी पर कई तरह से असर डालते हैं

अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी नासा द्वारा हासिल की गई तस्वीरों में सूरज का चेहरा सपाट दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे से उसके खास धब्बे (सनस्पॉट) भी गायब हैं। सूरज पर लगातार 16 दिन तक कोई धब्बा नहीं दिखा। यह इस बात का संकेत है कि सूरज अपने चक्र के 'सौर न्यूनतम' अथवा 'सोलर मिनिमम' चरण पर पहुंच गया है। सोलर मिनिमम की अवधि में सूरज पर गतिविधियां कम हो जाती हैं। यह चरण हर 11 वर्ष बाद आता है।

इस अवधि में सौर धब्बों और सौर लपटों की मात्रा कम हो जाती हैं। मुख्यतः उग्र रहने वाली सूरज की सतह कुछ शांत दिखाई देती है, लेकिन यह कृत्रिम शांति चुंबकीय तूफानों को जन्म देती है जो उपग्रहों में दखलंदाजी करते हैं, विमान यात्रा को प्रभावित करते हैं और विद्युत ग्रिडों को ठप कर देते हैं। सौर चक्र का चरम 'सौर अधिकतम' अथवा 'सोलर मैक्सिमम' कहलाता है। इस दौरान सतह पर लगातार धब्बे दिखाई देते हैं जिनमें से कुछ तो आकार में बृहस्पति ग्रह के बराबर होते हैं। चक्र के न्यूनतम चरण में कई महीनों तक एक सौर धब्बा भी नहीं दिखता और उसका चुंबकीय क्षेत्र भी कमजोर हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर पड़ने का अर्थ यह है कि ज्यादा ऊर्जा पृथ्वी की तरफ फेंकी जाती है। नासा का कहना है कि वर्ष 1650 से 1710 के बीच जब सूरज ने न्यूनतम चरण में प्रवेश किया था तब पृथ्वी का तापमान गिर गया था।

इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में तापमान बहुत नीचे आ गया था। इस शांत अवधि को 'माउंडर मिनिमम' भी कहा जाता है। नासा के अनुसार इस अवधि में सूरज की सतह पर बहुत कम सनस्पॉट प्रकट हुए और सूरज की चमक में मामूली गिरावट भी आई। इस अवधि में यूरोप और उत्तर अमेरिका डीप फ्रीज जैसा ठंडा हो गया। ग्लेशियर फैलकर घाटी के खेतों में पहुंच गए तथा नीदरलैंड की प्रसिद्ध नहरें नियमित रूप से जमती रहीं। अधिकतम अवधि में सौर धब्बों और सौर लपटों की तीव्रता बढ़ती है जिससे दुनिया में तापमान बढ़ता है। वर्ष 2014 में सूरज पर सौर धब्बे बड़ी संख्या में देखे गए थे। तब नासा ने कहा था कि न्यूनतम अवधि 2019 और 2020 के बीच शुरू होगी। खगोल वैज्ञानिक सौर न्यूनतम को ठंडे तापमान से जोड़ते हैं, क्योंकि सूरज की कुदरती हीटिंग प्रणाली धीमी पड़ जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है सूरज के कम धब्बे भी पृथ्वी के लिए समस्या पैदा करते हैं। सौर न्यूनतम चरण के नजदीक आने पर दूसरी गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।

इस दौरान सूरज के वायुमंडल में 'कोरोनल होल्स' विकसित होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं। सूरज के चुंबकीय क्षेत्र की सक्रियता कम होने पर ऐसा नियमित रूप से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज के तीन विशाल छिद्रों से निकलने वाली सोलर विंड पृथ्वी पर बमबारी करती है। चार्ज ऊर्जा कणों में वृद्धि हमारे ऊपरी वायुमंडल की केमिस्ट्री में बदलाव कर सकती है जिससे बिजली चमकने की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। विमानों में अधिक रेडिएशन दाखिल होने से लंबी उड़ान वाले यात्रियों और विमान चालकों को डेंटल एक्स-रे जितना रेडिएशन झेलना पड़ सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

नए मंत्रियों की चिंता

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऐसे कई नए नए मंत्री बने हैं जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी किस्मत भी यकायक खुलेगी। खैर अब मंत्री बन गए हैं तो यह चिंता सता रही है कि प्रधानमंत्री के सामने खुद को कैसे साबित किया जाए। आलम तो यह है कि इनमें से कई तो ऐसे हैं जो चुनाव जीतकर आ गए हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता कि पार्टी के घोषणापत्र में क्या था? अब मंत्रालय में बैठकर वे भाजपा का घोषणापत्र पलट रहे हैं। सरकार के सौ दिन के एजेंडे को जप रहे हैं और यह पूछने में भी पीछे नहीं हैं कि उन्हें और क्या करना चाहिए। जो राज्यमंत्री बने हैं उनके सामने दोहरी चुनौती है। पहले अपने सीनियर की अपेक्षाओं और उसके बाद प्रधानमंत्री की कसौटी पर खरा उतरने की। जाहिर है कि एक तो पहले कार्यकाल का दबाव और ऊपर से इतने कम समय में परिणाम देने की कवायद ने इन नए-नवेले मंत्रियों की नींद उड़ा दी है।

समझ का चक्कर

महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता समझ के फेर में ऐसे फंसे की चाहकर भी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं कर सके। दरअसल नेताजी की नाराजगी इस बात से थी कि राजनीति में उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर उन्हें अग्रिम पंक्ति में बैठने की जगह पांचवीं पंक्ति में सीट आवंटित की गई। हालांकि बाद में मामला कुछ और ही निकला। नेताजी की सीट पहली पंक्ति में वीवीआइपी सेक्शन में ही आवंटित थी, लेकिन उनके दफ्तर के सदस्य आमंत्रण का पास देखकर आगबबूला हो गए। पास पर नेताजी के नाम के आगे (वी) लिखा था, जिसे वे रोमन का पांच समझ बैठे। अब जब उन्हें यह पता चला कि वी का मतलब वीआइपी था तो फिर अपना सिर पकड़े बैठे है।

अरे साहब भी हिंदी...

शिक्षा मंत्रालय में इन दिनों अफसरों के हिंदी प्रेम की जबरदस्त चर्चा है। हालांकि उनके भीतर हिंदी के इस प्रेम का जागरण कोई स्वप्रेरणा से नहीं, बल्कि बड़े साहब की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए हुआ है। वजह बड़े साहब को हिंदी पसंद जो है। हालत यह है कि जो अफसर अब तक अपनी जुबान पर भूल से भी हिंदी को चढ़ने नहीं देते थे, वही बड़े साहब की मौजूदगी में होने वाली बैठकों में लच्छेदार हिंदी बोलते दिख रहे हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों में आए इस बदलाव से मंत्रालय के अधीनस्थ अधिकारी भी हैरान हैं। खास बात यह है कि अफसरों में हिंदी प्रेम का यह जागरण बड़े साहब के मंत्रालय में आमद के बाद हुआ है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कुछेक अफसरों ने बड़े साहब की किताबों को मंगवाकर उन्हें पढ़ना भी शुरू कर दिया है ताकि बड़े साहब को लुभाया जा सके। देखना होगा कि बड़े साहब पर अफसरों का यह जादू कितना और आखिर कब तक रंग दिखाता है।

गले पड़ा इस्तीफा

सरकार में राजनीतिक तौर पर नियुक्त हुए व्यक्ति आम तौर पर नई सरकार के गठन से पहले इस्तीफा देते हैं। नीति आयोग के एक सदस्य ने इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके इस कदम के बाद बाकी सदस्यों को भी इस्तीफा देना पड़ा। बताया जाता है कि कुछ लोग तो इस्तीफा न देने पर भी अड़े थे। ऐसे लोगों को समझा-बुझाकर इस्तीफा दिलवाया गया। बहरहाल जब प्रधानमंत्री ने इस आयोग का पुनर्गठन किया तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाले सदस्य महोदय का नाम आदेश में नहीं था। बहरहाल इस आदेश के बाद आयोग के बाबुओं के बीच चर्चा गरम है। कई बाबू उम्मीद जता रहे हैं कि उक्त सदस्य महोदय को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह इस्तीफा उनके गले की फांस जरूर बन गया। अब वह भी बस टकटकी लगाए हुए ही देख रहे हैं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस